SI. No	Name of Officer	Transferred		Year of transfer
		From	To	
L	Smt. S. Mehta, IAS (RR: 79)	U.P.	AGMUT	1981
2.	Shri A. Mukherjee, IAS (RR: 83)	Gujarat	W. Bengal	1986
3.	Shri R. S. Mann, IAS (RR: 65)	Haryana	Punjab	1986

NO officer from IPS/IFS has been transferred to his/her Home State on ground of marriage, as per the information given by MHA and Ministry of Environment & Forest, respectively.

Premature Retirement in Central Government

7365. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the minimum period of service after which an employee of Government of India can claim premature retirement and the benefit of 5 years for calculating pension and gratuity;

(b) the reasons for not allowing Central Government employees to seek premature retirement and the benefit after rendering 15 years service which can obviate the unemployment problem; and

(c) whether this point has been referred to the Fifth Pay Commission for giving concrete suggestions in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) Under Rule 48-A of the Central Civil Services (Pension) Rule, 1972, any Central Government employee at any time after he has completed twenty years' qualifying service, may, by giving notice of not less than three months in writing to the appointing authority, retire from service. Under Rule '48-B of the aforesaid rules the qualifying service as on the date -of intended retirement of the Government servant retiring under Rule 48-A shall be increased by the period not exceeding five years, subject to the condition that the total qualifying service rendered by the Government servant does not in any case exceed thirty-three years and it does not take him beyond the date of superannuation.

(b) and (c) The conditions of Central Government employees are under consideration of the Fifth Central Pay Commission, which would also be looking into issues relating to premature retirement of Central Government servants.

Norms for Expenditure under Indira Awaas Yojana

7366. SHRI PR AG AD A KOTAIAH:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the norms of permissible expenditure under the Indira Awaas Yojana for construction of houses are being revised;

(b) if so, what are the new norms;

(c) if not, whether a proper house can be constructed with an amount of Rs. 10,500 per house; and

(d) when will the norms be revised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND

EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAM BHAI PATEL): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Indira Awaas Yojana (IAY) basically provides houses to the people of weaker sections such as Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the people below poverty line. In other words, the scheme provides houses to the poorest of the poor. The minimum need requirement is at least one roomed house. The present cost norm for the house in plain areas is Rs. 14,000 and in hilly and difficult areas Rs. 15,800 (including sanitary and infrastructure facilities). It is considered that with low cost technology using locally available materials and self-help by the beneficiary, a one roomed house can be constructed within these cost limits.

(d) The cost norms for IAY houses are revised from time to time keeping in view the escalation in cost of material, labour etc. The present cost norms of IAY houses have been revised w.e.f. 1.1.1994.

त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक और शैक्षणिक विकास केन्द्र, पथराही को दी गई निधियां

7367. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत "कापार्ट" द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक विकास केन्द्र, पथराही, झंझारपुर (आर०एस०) जिला मधुबनी, बिहार को कुल कितनी राशि दी गई है;

(ख) क्या यह सच है कि "कापार्ट" ने बिहार के सासाराम जिले में काराकट और देहरी प्रखंडों में इंडिया मार्क-II चापाकल गाड़ने के लिए 1991 में इस संगठन को सात लाख रुपये से अधिक की राशि दी थी;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत गाड़े गए इंडिया मार्क-II चापाकलों की और इससे लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ङ) इस संगठन द्वारा गाड़े गए चापाकलों की कुल संख्या कितनी है और इनमें से कितनी चापाकल ठीक तरह से काम कर रहे हैं और कितने खराब पड़े हैं; और

(च) क्या सरकार इस तथ्य की जांच कराएगी कि निर्धारित मानदंड न अपनाए जाने के कारण ये चापाकल लगाए जाने के बाद खराब हो गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत कापार्ट द्वारा सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र, पथराही, झंझारपुर, जिला मधुबनी, बिहार को 58.17 लाख रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है।

(ख) जी हां, बिहार के सासाराम जिले के काराकट और देहरी प्रखंडों में हैंडपम्पों को लगाने के लिए कापार्ट ने 1991 और 1992 में सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र को 7 लाख से अधिक की राशि संस्वीकृत की है। तथापि, यह राशि स्थानीय पी० एच०-6 हैंडपम्पों को लगाने के लिए न कि इंडिया मार्क-2 हैंडपम्पों को लगाने के लिए संस्वीकृत की गई थी।

(ग) 180 पी०एच०-6 हैंड पम्प लगाए गए हैं और लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 27,000 है।

(घ) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक लगभग 84,750 लाभार्थियों को कवर किया गया है।

(ङ) और (च) सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र द्वारा लगाए गए हैंड पम्पों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

स्थानीय पी०एच०-6	300
इंडिया मार्क-2	159
कुल:	459

अब तक, कापार्ट को इस संगठन द्वारा लगाए गए हैंड पम्पों के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है। तथापि, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए कार्यों के स्तर का मूल्यांकन करने सहित संगठन की कार्य-प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए कापार्ट द्वारा एक जांच समिति गठित की गई है।